RAJYA SABHA

Wednesday, the 24th February, 1965/the 5th Phatguna, 1886 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी कर्मचारियों को मकान का अलाट किया जाना

*121. **श्री भगवत नारायण भार्गव :** क्या निर्माण तथा आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक सरकारी मकान अलाट नहीं किया गया है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो राज्यों से डेपुटेशन पर आये हैं और सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे हैं तथा जिनको गत पांच वर्षों में सरकारी मकान अलाट किये गये हैं ?

-^[ALLOTMENT OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION TO GOVERNMENT EMPLOYEES

*121. SHRI B. N. BHARGAVA : Wilt the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of Class I, Class II, Class 111 and Class IV employees in Delhi who have not been allotted Government residential accommodation so far; and

(b) the number of them in each class who have come on deputation from the Slates and are working in the Public Under takings and have been allotted Government residential accommodation during the last five years ?]

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) सरकारी क्वार्टरों को अलाट करने के लिए वेटिंग लिस्ट नौकरी की क्लास के मुताबिक नहीं बनाई जाती बल्कि उनकी तनख्वाह के आधार पर । अलाटमेंट की स्थिति को बताने के लिए एक विवरण राज्य सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

दिल्ली में जनरल पूल में निवास स्थानों के अलाटमेंट की स्थिति निम्न प्रकार है:—

वास का टाईप	इस टाईप के लिए पात्र अधिकारियों की वेतन श्रेणी	निवास स्थान को अलाट किये गये अधिकारियों की संख्या	अलाटमेंट के लिए इन्तजार करने वाले अधिकारियों की संख्या
I	110 से कम	12,246	14,131
II	110 से 249 रुपये	11,584	34,738
III	250 से 399 रुपये	4,301	9,946
IV	400 से 699 रुपये	4,392	4,386
V	700 से 1299 रुपये	1,958	2,185
VI	1300 से 2249 रुपये	586	627
VII और VIII	2250 रुपये और इससे ऊपर	244	82
	कुल	35,311	66,095

पिछले पांच वर्षों में उन अधिकारियों को, जोकि राज्यों से डेपुटेशन पर आये हैं और पब्लिक अन्डरटेकिंग में काम कर रहे हैं, जनरल पूल में से निम्न प्रकार निवास स्थान अलाट किये गये हैं:—

टाईप	VII	8
टाईप	VI	3
टाईप	V	4
कुल		15

tUra. MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI MEHR CHANP KHANNA) : (a) and (b) Waiting list for the purpose of, allotment of Government quarters is not maintained according to the class of service to which officers belong, bLit on the basis of the range of their emoluments. A statement showing the position of allotments is placed on the Table of the Rajya Sabha.

STATEMENT

The position about allotment of residences in the general pool in Delhi is as under :—

Type of accom-modation	Pay ranges of officers entitled to that type	No. of officers allotted residences	No. of officers waiting for allotment
I	Below Rs. 110	12,246	14,131
II	Rs. 110 to 249	11,584	34,738
III	Rs. 250 to 399	4,301	9,946
IV	Rs. 400 to 699	4,392	4,386
V	Rs. 700 to 1299	1,958	2,185
VI	Rs. 1300 to 2249	586	627
VII and VIII	Rs. 2250 and above	244	82
	TOTAL	35,311	66,095

The number of general pool residences allotted during the last five years to the officers who have come on deputation from the States and are working in the Public Undertakings is as under :—

Type VII	8
Type VI	3
Type V	4
TOTAL	15]

श्री भगवत नारायण भार्गव : यह जो स्टेटमेंट रखा गया है उससे मालूम होता है कि जो लोग 110 रु० से 249 रु० के बीच तनख्वाह पाते हैं, ऐसे अफसरों की संख्या 34,738 है जिनको कि अभी तक मकान नहीं दिये गये हैं। जो 1300 रु० से 2250 रु० के बीच तनख्वाह पाते हैं और नौकरी में हैं उन्हें अधिकतर तादाद में मकान दे दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार की नीति के अनुकूल है कि जिन लोगों को कम तनख्वाह मिलती है और जिन्हें दिल्ली में मकान मिलने में कठिनाई होती है उनकी संख्या इतनी अधिक हो और जो बड़े अफसर हैं, जो मकान का ज्यादा किराया दे सकते हैं उनकी तादाद कम हो और उन्हें मकान भी सरकार की तरफ से जल्दी मिल जाते हैं ?

†[ ] English translation.

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो कुछ माननीय सदस्य ने फरमाया वह बिल्कुल दुरुस्त है। जो गरीब लोग है, जिनको तनख्वाह कम मिलती है, उनकी जरूरत भी ज्यादा है और उनको मकान ज्यादा मिलने चाहिये। इस समय ऊपर के दर्जे वालों के लिए मकान ज्यादा है लेकिन हमने अब यह फैसला किया है और इस बात पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी सहमत है कि जो छोटे दर्जे के आदमी हैं, जो एक, दो, तीन, चार कैटेगरी में हैं, अब उनके लिए ही मकान बनाये जायेंगे। इन लोगों का भी परसेन्टेज उसी लेवल पर लाया जायेगा जो बड़े कैटेगरी के लोगों का है। अब हमने इन लोगों के लिए मकान बनाने शुरू कर दिये हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे-जैसे हमको सामान मिलता जायेगा वैसे-वैसे हम इन कैटेगरी के लोगों के

लिए भी ज्यादा तादाद में मकान बना सकेंगे ।

श्री भगवत नारायण भार्गव : जो 34 हजार अफसर काम कर रहे हैं वे कितने वर्षों से वेटिंग लिस्ट पर पड़े हुए हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह दुरुस्त है कि चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो या मद्रास हो, इन जगहों पर हमारे मकानों की संख्या बहुत कम है। 1 लाख 15 हजार मकानों के मुकाबले में दिल्ली में 36 या 37 हजार ही मकान हैं । अब हम पांच-सात हजार मकान बना रहे हैं । पिछले साल भी हमने बनाये थे और उम्मीद है कि जैसे ही हमें ज्यादा सीमेंट और स्टील मिल जायेगा हम उतनी तेजी के साथ ज्यादा मकान बना सकेंगे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं हम इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सामान की इस समय कमी है ।

श्री भगवत नारायण भार्गव : जो लोग राज्यों से डेपुटेशन में आये हुए हैं और पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या नीति है ? इन लोगों को मकान नहीं दिया जाता है और पांच वर्षों में केवल 15 आदमियों को ही मकान दिया गया है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो लोग पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है । लेकिन सवाल यह है कि जब ज्यादा लोग भूखे हों, रोटी अपने पास कम हो और लेने वाले ज्यादा हों तो कोशिश यह होती है कि और आदमियों को घर में न बुलाया जाय । हमारे पास पहले ही बहुत कम जगह है इसलिए हम दूसरों का भार लेना नहीं चाहते हैं ।

इसके साथ ही साथ दूसरी चीज यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के सर्वेन्ट्स हैं उनका जनरल पूल पर कोई हक नहीं है । जब हम अपने आदमियों को नागपुर, बम्बई या मद्रास में भेजते हैं तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट हमारे आदमियों को मकान नहीं देती है । लेकिन जब हमारे आदमी किसी पब्लिक अन्डरटेकिंग में काम करने जाते हैं तो हम उन्हें मकान देने की कोशिश करते हैं और मकान देने में इन लोगों का ध्यान रखते हैं ।

SHRI I. K. GUJRAL : Sir, in view of the fact that socialist society is our objective, and particularly it must express itself in housing, has the Government now come to the conclusion that allotment of housing j should not be according to the salary but according to the social needs of a person ?

SHRI MEHR CH\ND KHANNA : li is a very big question. Up till now we have been dealing with it on the basis of pay ranges. We are not able to tackle this problem even on this basis. So it will be very difficult for me now to make a diversion or departure of a very basic and fundamental nature.

COL. B. H. ZA1DI : On more than one occasion, Pandit Jawaharlal Nehru had stated that no quarter meant for Class IV employees should have less than two rooms. Is that policy being implemented in the case of new construction, and what is the position regarding houses already existing which have only one room ?

SHRI MEHR CHAND KHANNA : What the late Prime Minister indicated was that in future for this lower category of persons we should not construct houses with less than two rooms: we should give two rooms instead of one. We are adopting that .policy now and working on those lines.

SHRI G. M. MIR : J would like to know what decision has been taken in the Housing Ministers' Conference at Chandigarh with regard to housing accommodation for the poor people.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: Sir, these are two separate questions. This is in regard to the general pool accommodation. Thai is social housing.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : जैसा कि श्रीमान् ने अभी बतलाया कि करीब 6-4 हजार कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं मिले है और क्वार्टर की समस्या के बारे में श्रीमान यह कहते हैं कि सीमेन्ट और लोहे की कमी है । श्रीमान् ने यह भी कहा कि अगर यह चीज मिल जाय तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब सहयोग देने के लिए तैयार हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर सीमेन्ट और लोहे की कमी है तो उसकी जगह पर दूसरा सब्सिटयूट यानी चूना, ईंट, पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता है ताकि मकान की समस्या हल हो सके ।

दूसरी बात यह है कि शासकीय आधार के अलावा लोगों को, रुपया उधार दिया जाना चाहिए ताकि वे खुद भी या कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा मकान बना सकें । इस दिशा में श्रीमान् का विभाग क्या कार्य-वाही कर रहा है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने यह कभी नहीं कहा कि हम दूसरा तरीका नहीं अपना रहे हैं, वह भी हम कर रहे हैं । मैंने कहा कि हम हर साल हजारों की तादाद में मकान बना रहे हैं । आज हमारे पास चूने की कमी नहीं है बल्कि सीमेंट और स्टील की कमी है । अगर यह चीजें हमें मिल जायें तो हम ज्यादा तेजी के साथ मकान बना सकते हैं ।

दूसरा जो उनका सवाल है उसका ताल्लुक सोशल हाउसिंग स्कीम के साथ है लेकिन यह जो सवाल है वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का है जो जनरल पूल एकमोडेशन के अन्दर आते हैं । जो सोशल हाउसिंग स्कीम है उसको हम दूसरे तरीके से चला रहे हैं । इस स्कीम के अन्तर्गत, कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन्डस्ट्रियल वर्कर्स हैं, लो कैटेगरी के आदमी हैं, स्लम ड्वैलर्स हैं और इन सब की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं ।

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI : The-hon. Minister has just stated that he is building houses for Class II, III and IV employees of the Government. Does he know that almost all the Class I employees of the Government have got accommodation round about their offices, in spite of the fact that they have cars at their' disposal ? May I know whether he is contemplating to build houses for Class II, III and IV employees nearer to their offices?

SHRI MEHRCH\ND KHANNA : I never excluded Class I. When I talked of lower category, I meant from I to IV. Our policy now is to build offices in colonies. In fact, in Ramakrishnapuram and many other colonies we are building offices so that these Government employees work there and also live there.

SHRI A. D. MANI : Sir, according to the Statement as many as 66 thousand persons are awaiting allotment of residential accommodation. The hon. Minister has said th;il he is trying to build more houses provided material for the construction is available. May I ask him what is the plan that the Ministry is having for the next five years for the construction of houses to accommodate these officers ?

SHRI MEHR CHAND KHANNA : As far as the Fourth Five Year Plan is concerned, we are making an allocation of about Rs. 100 crores—that is what I have suggested to the Planning Commission— for the construction of houses in the Government sector as against Rs. 25 or Rs. 30 crores provided in the Third Plan.

श्री गिरिराज किशोर कपूर : मंत्री महोदय ने फर्माया कि हम ऐसी स्कीम बना रहे हैं कि जैसे ही लोहा और सीमेंट मिल गया, मकान बन जायेंगे । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी भी योजना बनाई है या नहीं कि एक साल के अन्दर कितने एम्प्लाइज को मकान दे दिये जायेंगे, दूसरे

साल के अन्दर कितनों को दिये जायेंगे और पांच साल में, जितने एम्प्लाइज आज मकान के बगैर हैं, उन सब को मकान मिल जायेंगे ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : पहले तो मैं दोहराना यह चाहता हूं, जनाबवाला, कि अगर मेरे पास चूना और सीमेंट हो जाय तो मैं ज्यादा तेजी से मकान बना सकता हूं । मैंने यह नहीं कहा कि मकान नहीं बन रहे हैं । मैंने अभी अर्ज किया था कि इस वक्त भी हम दिल्ली में कोई चार-पांच हजार मकान रामकृष्णपुरम् में बना रहे हैं । इसी तरीके से दूसरे शहरों में भी हम बना रहे हैं । हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट चन्द दिनों के अन्दर आपके पास आ जायगी और उसमें आपको तमाम इनफार्मेशन मिल जायगी कि हम कितने मकान बना रहे हैं और अगले साल का क्या प्रोग्राम है । लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में मेरा इरादा यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कम अज कम एक सौ करोड़ रुपया खर्च किया जाय ताकि जितना भी गैप ब्रिज हो सकता है, उसको ब्रिज करने की कोशिश करें ।

SHRI B. K. GA1KWAD : May I know whether it is a fact that the Government servants have formed their own co-operative housing societies and, if so, what is their number and whether it is a fact that some Scheduled Caste Government employees have formed a housing society and demanded Government lands and instead of giving them lands, those lands are being sold by the Government by public auction '.'

SHRI MEHR CHAND KHANNA : I go on repeating myself that there is a confusion as regards construction undertaken by the Government in the general pool and the social housing scheme. All these cooperative societies and other schemes cover the social housing scheme. We are dealing with them in the States as well as in the Union Territories. If the Member wants specific information about a particular scheme in any particular State, I shall give the answer. As regards the other question about auctioning of land, or sale of land, it is right that the land prices are shooting up but it will be very wrong on my part to start allotting lands on a negotiated basis to anybody. That is likely to cause complications and may not be very desirable. So we do auction lands but those lands naturally are purchased by those who can afford to pay, but in the social housing scheme we have an entirely different pattern.

SHRIMATI SHAKUNTALA PAR \NJ-PYE : What is happening to the prefabricated housing scheme ?

SHRI MEHR CHAND KHANNA : As regards the prefabricated housing scheme, we have made very good progress. The factory is doing very good work and according to our new experiment, we should be able to undertake prefabricated housing on a very large-scale. We have even put up some prototype houses near Mehrauli. If the hon. Member is interested, 1 shall see that she is shown the new houses that we are putting up.

श्री उद्धवराव साहेबराव पाटिल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अभी कितने ऐसे मकान तैयार हैं जो एलाट नहीं किये गये हैं ? महज पानी या इलेक्ट्रिसिटी का इन्तजाम न होने की वजह से जो मकान एलाट नहीं किये गये हैं, वे कितने हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह सवाल तो आज ही पूछा गया है लेकिन अनस्टार्ड है । आनरेबिल मेम्बर अनस्टार्ड क्वेश्चन की इनफार्मेशन स्टार्ड क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है । इस वक्त रामकृष्णपुरम् में आठ, नौ सौ मकान ऐसे हैं जो तैयार हो चुके हैं, लेकिन पानी न होने की वजह से हम उनको एलाट नहीं कर सके हैं । हमने कारपोरेशन से यह मामला दो तीन मरतबा उठाया है । हमें उन्होंने कहा है कि शायद दो तीन महीने के अन्दर वे पानी का प्रबन्ध कर देंगे, तब हम वह मकान एलाट कर सकेंगे ।